



शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को मंजूरी

एक लाख से ज्यादा और मकानों को मंजूरी, मध्य प्रदेश के लिए 57131 आवास और
तमिलनाडु के लिए 24576 आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास मंजूरी में तमिलनाडु को पीछे छोड़
सबसे आगे पहुंचा मध्य प्रदेश

अब तक 2151 शहरों एवं कस्बों में शहरी गरीबों के लिए 18.75 लाख मकानों को
मंजूरी

Posted On: 26 APR 2017 6:35PM by PIB Delhi

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 4200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,00,537 और मकानों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 1,00,466 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है। यह शहरी क्षेत्रों में किफायती मकानों के लिए वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मंजूर किये गये 32,713 करोड़ रुपये के निवेश से 307 प्रतिशत ज्यादा है।

नवीनतम मंजूरी के साथ ही मंत्रालय ने अब तक 34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 2151 शहरों एवं कस्बों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए 18,75,389 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं, दूसरी ओर 2004-2015 अवधि के दौरान 32,009 करोड़ रुपये के स्वीकृत निवेश के साथ 13.80 लाख मकानों को मंजूरी दी गई थी।

अब तक स्वीकृत किये गये कुल निवेश में 29409 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त सहायता और लाभार्थियों का अंशदान शामिल है।

नवीनतम मंजूरी के तहत मध्य प्रदेश को 57131 मकान, तमिलनाडु को 24576, मणिपुर को 6231, छत्तीसगढ़ को 4898, गुजरात को 4261, असम को 2389, केरल को 643, झारखंड को 331 और दमन एवं दीव को 77 मकान हासिल हुए हैं।

कुल 2,66,842 मकानों को दी गई स्वीकृति के साथ मध्य प्रदेश पहली बार 18,283 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दी गई मंजूरीयों के मामले में पहली बार नंबर-1 बना है। तमिलनाडु 9,112 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले 2,52,532 मकानों के साथ दूसरे नंबर पर है।

प्रमुख राज्यों में स्वीकृत मकानों और मंजूर परियोजना निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	मंजूर किफायती मकानों की संख्या	स्वीकृत निवेश (करोड़ रुपये में)
मध्य प्रदेश	2,66,842	18,283
तमिलनाडु	2,52,532	9,112
आंध्र प्रदेश	1,95,047	10,697
गुजरात	1,48,948	9,772
कर्नाटक	1,46,548	6,288
पश्चिम बंगाल	1,44,369	5,870
महाराष्ट्र	1,26,081	13,458
बिहार	88,293	3,909
तेलंगाना	82,985	4,998
झारखंड	64,898	2,423
ओडिशा	48,855	2,108
त्रिपुरा	45,908	1,264
पंजाब	42,681	1,199
राजस्थान	37,856	2,646
छत्तीसगढ़	34,973	2,962
केरल	28,918	963
असम	26,742	801
उत्तर प्रदेश	20,682	1,056
मणिपुर	15,979	414
नगालैंड	13,560	335
मिजोरम	10,459	219

उत्तराखंड	7,904	510
जम्मू-कश्मीर	6,243	292
हिमाचल प्रदेश	4,890	222
हरियाणा	4,299	338

अब तक जितने मकानों को मंजूरी दी गई है, उनमें से 6,89,829 मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जबकि 1,00,395 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

वीके/आरआरएस/जीआरएस-1154

(Release ID: 1488693) Visitor Counter : 5

